International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 03-01-2022, Accepted: 18-01-2022, Published: 03-02-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 86-92

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एवं भारत

सत्येंद्र कुमार[1], आशा राणा[2]

[1] शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राधे हरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उत्तराखंड, भारत

[2] प्रोफ़ेसर, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राधे हरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उत्तराखंड, भारत

सारांश

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना "BELT & ROAD" का हिस्सा बनाया गया है तथा इस गलियारे को BRI परियोजना की रीढ़ कहा जा रहा है चीन इसके माध्यम से अपनी 'मार्चिंग वेस्टवर्ड्स पॉलिसी के अनुरूप अपने पश्चिमी, क्षेत्रों को खोलने और विकसित करने की योजना बना रहा है क्योंकि यह गलियारा पश्चिमी चीन को सीधे अरब सागर से जोड़ेगा। लेकिन यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जो कि एक विवादित स्थल है तथा भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है इसलिए भारत ने इसे अपनी सम्प्रभुता का हनन मानकर इस गलियारे का विरोध किया है। इसके अलावा यह भारत के सामरिक हितों के लिए भी एक चुनौती प्रस्तुत करता हैं एवं यह अरब सागर में भारत की एकछत्रता को भंग करने की भी कोशिश करता है तथा दक्षिण एशिया में बढ़ते चीन के कदमों की आहट भी सुनाता है और भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ी महाशक्ति है इसलिए यह एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश भी दिखाता है। भारत इस गलियारे पर क्या प्रतिक्रिया देता है तथा अपने सामरिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारत क्या विकल्प अपना सकता है इसी को जानने का प्रयास इस लघु शोध में किया गया है।

मूल शब्दः चीन–पाकिस्तान, आर्थिक, गलियारा, भारत

प्रस्तावना

हाल के वर्षो में, आर्थिक गलियारे वैश्वीकरण के युग में क्षेत्रीय सहयोग और विकास के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरे हैं। ग्रेटर मेकांग उप–क्षेत्र (जीएमएस) में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गलियारों के एक नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के अनुभव के बाद, इसी तरह की पहल को अब एशिया के विभिन्न हिस्सों में पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक केन्द्रों के साथ जोड़कर आर्थिक विकास को गति देने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सीमापार उत्पादन नेटवर्क का एकीकरण कर बाजारों तक पहुंच में सुधार करना भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम दक्षिण एशिया में दो आर्थिक गलियारों का निर्माण करने का प्रस्ताव था, जो दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। 22 से 23 मई 2013 तक पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान, चीन के प्रमुख ली केकियांग ने, चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में काशगर को ग्वादर के दक्षिण–पश्चिमी पाकिस्तानी बंदरगाह से जोड़ने के लिए चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) प्रस्तावित किया। यह यात्रा उनकी भारत यात्रा के तुरन्त बाद हुई थी, जिसके दौरान भारत और चीन बीसीआईएम (बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार) गलियारे के लिए गुंजाइश तलाशने पर सहमत हुए थे। ये दोनों प्रस्ताव दक्षिण एशिया और व्यापक एशिया–प्रशांत क्षेत्र एवं कुछ अन्य क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से चीन इसके माध्यम से अपनी 'मार्चिंग वेस्टवर्ड्स पॉलिसी (वांग 2012) के अनुरूप अपने पश्चिमी, क्षेत्रों को खोलने और विकसित करने की योजना बना रहा है और यह सब वह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) के तहत कर रहा है जोकि चीनी विदेश नीति में एक नई पहल है जिसे 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा व्यक्त किया गया था, ओबीओआर परियोजना के दो घटक हैः पहला, भूमि आधारित 'न्यू सिल्क रोड, और दूसरा, 21 वीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग'। एक साथ पूर्वी एशिया, मध्य और दक्षिण एशिया तथा यूरोप को जोड़ने वाले पूरे यूरेशियन लैंडमास में फैले परिवहन गलियारों, पाइपलाइनों, बंदरगाहों और फाइबर–ऑप्टिकल केबलों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (एसआरईबी) बनाने का लक्ष्य है। इन पहलों के साथ, नवंबर 2014 में, चीन ने बुनियादी ढांचे, संसाधनों, औद्योगिक सहयोग, वित्तीय सहयोग और 'BRI' में साथी देशों के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, निवेश और वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सिल्क रोड फंड की घोषणा की। इससे पहले चीन ने एशिया के गरीब हिस्सों में सड़कों, रेलवे और अन्य परिवहन लिंक के निर्माण के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी।

दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों ने इन चीनी पहलों का स्वागत किया है लेकिन भारत ने अभी तक परियोजना के लिए हामी नहीं भरी है। भारत में कई पर्यवेक्षक इन पहलों को व्यापक एशिया–प्रशांत क्षेत्र में अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने और दक्षिण एशिया में भारत के रणनीतिक घेराव को हासिल करने के चीनी प्रयास के रूप में देखते हैं, हालांकि, चीन के साथ भारत के संबंधों में पिछले दशक में काफी सुधार हुआ है, दोनों देशों ने विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक साथ काम किया है, जिनमें हाल ही में स्थापित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक शामिल है। लेकिन सीमा विवाद जैसे विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दे अनसुलझे ही रहे। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते संबंधों के बारे में भी गहराई से चिंतित है, जिसका उद्देश्य भारत के सामरिक हितों को हानि पहुंचाना हो सकता है।

यह सच है कि क्षेत्रीय वातावरण में सहयोग के मामले में भारत की सोच स्थिर ही रही है तथा भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग की विविध प्रक्रियाओं को संचालित करने में तथा उनको गतिशीलता प्रदान करने में एवं क्षेत्र की जटिलता तरलता और बारीकियों को समझने में असफल रहा है एवं CPEC का यह प्रस्ताव भी अभी तक भारत के खिलाफ रहा है क्योंकि यह भारत की सम्प्रभुता से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि कूटनीति की मदद से इसे सही प्रकार से लागू किया जाये तो यह भारत के लिए आशाजनक हो सकता है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नए द्वारा खोल सकता है।

Source: *Xinhua* n.d

Map I: The New Silk Road and 21st Century Maritime Silk Route

चित्र 1

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

प्रस्तावित आर्थिक गलियारा चीन के उत्तर–पश्चिमी प्रांत शिनजियांग को ग्वादर के पास पाकिस्तानी बंदरगाह के साथ जोड़ेगा। जो कि लगभग 3000 किलोमीटर (1800 मील) की सड़कों का एक नेटवर्क है, जो पाकिस्तान को उसके लिए आवश्यक आर्थिक अवसरंचना प्रदान करता है, विशेष रूप से बिजली उत्पादन संयंत्र एवं चीन को हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान कर ये विश्व के सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग में प्रवेश करा देगा। चीनी–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जहां स्थित हैं वहां सिल्क रोड़ इकोनॉमिक बेल्ट और 21 वीं सदी के मैरीटाइम सिल्क रोड मिलते हैं। इसलिए, यह ''बेल्ट एवं रोड'' पहल का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है।

पाकिस्तान ने बड़े उत्साह के साथ इस आर्थिक गलियारे के लिए प्रीमियर ली के प्रस्ताव को दोहराया और गलियारे की दीर्घकालिक योजना पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चुनाव के बाद अपने पहले भाषण में, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस परियोजना का उल्लेख किया, हालांकि उनका भाषण अनिवार्य रूप से पाकिस्तान के घरेलू मुद्दों के बारे में था और किसी भी अन्य विदेश नीति के विवरण का अभाव था। बाद में, जुलाई 2013 में चीन की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने CPEC के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और न केवल पाकिस्तान और चीन बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, दोनों देशों ने CPEC के लिए संयुक्त सहयोग समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता अहसान इकबाल, (पाकिस्तान के योजना एवं विकास मंत्री) और चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के उपाध्यक्ष झांग जियाओकियांग ने की। इस संयुक्त समिति की पहली बैठक 27 अगस्त 2013 को इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी। CPEC परियोजना को चीनी

राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान 20 से 21 अप्रैल 2015 के दौरान हुए समझौतों और 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ एक महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली।

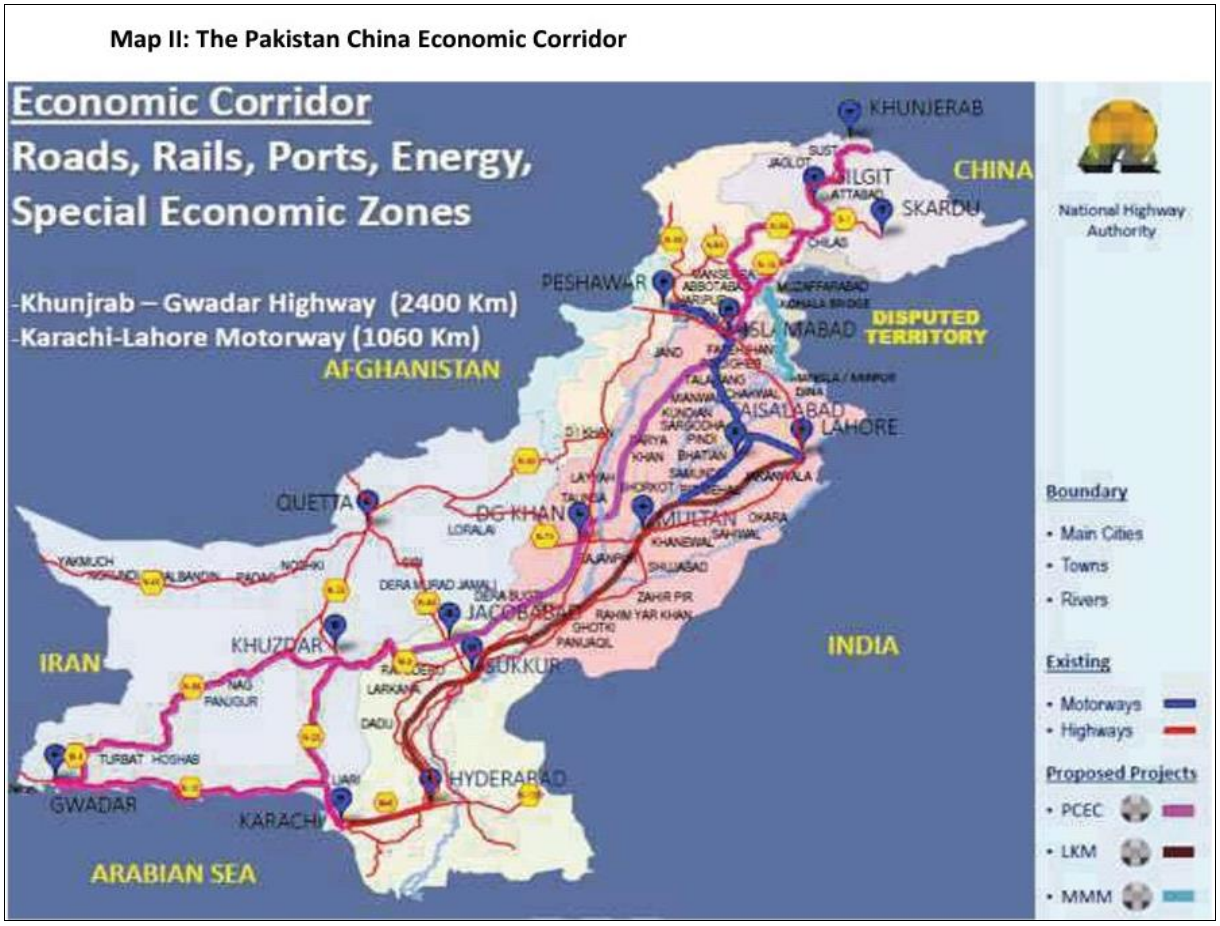

चित्र 2

पहली नजर में, प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के उभरते स्वरूप बस लुभावने प्रतीत होते हैं। योजना के अनुसार, कई औद्योगिक पार्को और आर्थिक क्षेत्रों, बांधों और ऊर्जा स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। जो विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होंगें जो कि काशगर–ग्वादर मार्ग के साथ–साथ पाकिस्तान की पूरी लंबाई और चौड़ाई (मानचित्र प्प्) का निर्माण करेंगें। इस पूरे सेट–अप की कुल लागत 45 बिलियन यूएस डॉलर तय की गयी थी जो 62 डॉलर बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस परियोजना के 2030 में पूरा होने की उम्मीद है।

CPEC में चीन तथा पाकिस्तान के हित एवं चुनौतियाँ

चीनी निवेश नीति एवं चीनी हित

2001 में चीन की ''गो ग्लोबल'' पहल के लागू होने के बाद से, चीन सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा नियंत्रण, अनुमोदन प्रक्रियाओं और निवेश प्रतिबंधों में ढील दी है। 2003 के बाद से, निजी स्वामित्व वाले उद्यमों को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने की अनुमति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। इस समय के बाद से, चीनी FDI निवेश तेजी से बढ़ा जो 2003 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था वह 2011 में 70 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गया है। जबकि राज्य स्वामित्व वाले उद्यम सबसे बड़े निवेशक बने हुए हैं– मुख्य रूप से पेट्रोलियम, निर्माण, दूरसंचार और शिपिंग– निजी कंपनियों में, जैसे लेनोवो ने विदेशों में निवेश करना शुरू कर दिया है।

हालांकि चीन का FDI का अधिकांश हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर निर्देशित रहा है, 2003 के बाद से, चीन ने दक्षिण एशिया पर अपना राजनयिक और आर्थिक ध्यान बढ़ाया है। यह समझना मुश्किल है कि चीन के पास दक्षिण एशिया के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए भू राजनीतिक कारण हैं या नहीं। एक ओर, चीनी उद्देश्यों को निर्यात–आधारित विकास रणनीतियों और व्यापार मार्गो का विस्तार करने की इच्छा के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी ओर, चीन के लिए इस क्षेत्र के साथ संबंध राजनयिक दबाव बनाने और अपनी सेना की पहुंच बढ़ाने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस तरह की धमकी को नजरअंदाज किया जा सकता था यदि चीनी सेना, विशेष रूप से पीपुल्स आर्म्ड पुलिस ने भारत में सीमा घुसपैठ करते समय संयम दिखाया होता। चीन द्वारा बार–बार सीमा घुसपैठ का इस्तेमाल किया गया है इसीलिए भारत को रक्षात्मक बनाए रखने के लिए चीन से सावधान रहना चाहिए। हर बड़ी द्विपक्षीय यात्रा के बाद, इस तरह की घटनाएं गंभीर आयाम लेती हैं। चीन ने अपने हालिया नीति निर्माणों में, विवाद समाधान पर जोर नहीं दिया है जोकि एक गंभीर मुद्दा है।

CPEC पर भारी निवेश करके, चीन ने अपने स्वयं के कई हितों को पूरा करने का प्रयास किया है। लगभग 45.6 बिलियन डॉलर की ऊर्जा और ढांचागत परियोजनाएं बीते 6 वर्षो में पूरी हो चुकने के कगार पर हैं, जहां चीनी कंपनियाँ

परियोजनाओं को लाभ कमाने वाली संस्थाओं के रूप में संचालित कर सकेंगी। मीडिया रिपोर्टो के अनुसार, चीनी राज्य और इसके बैंक चीनी कंपनियों को काम करने के लिए उधार देंगें, जिससे यह चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था पर सीधे प्रभाव के साथ एक व्यावसायिक उद्यम बन जाएगा इसके अलावा बीजिंग का मानना है कि आर्थिक विकास और स्थिरीकरण के बिना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चीन के उत्तर–पश्चिम में सुरक्षा समीकरणों को कमजोर कर देंगें। आर्थिक गलियारे का उद्देश्य आर्थिक रूप से चीन के मुस्लिम बहुल उत्तर–पश्चिम क्षेत्र को ग्वादर से जोड़कर आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करना है। आर्थिक गलियारा मध्य पूर्व से चीन के ऊर्जा आयात के लिए मार्ग को लगभग 12000 किलोमीटर तक छोटा कर देगा

पाकिस्तान का हित

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो दक्षिण एशिया में चीन की वो रस्सी बनना चाहता है जिसके सहारे चीन अरब सागर तक पहुँच सके और इसके बदले चीन से अपने यहाँ ऊर्जा संकट हल करने की तथा बुनियादी ढांचे की समस्या को हल कराना चाहता है। प्रस्तावित परियोजना पाकिस्तान के जीर्ण–शीर्ण बिजली के बुनियादी ढांचे को ठीक करने का प्रयास करेगी, जो एक जरूरी और लंबी–अनसुलझी समस्या है विशेषज्ञों का कहना है, प्रत्येक वर्ष देश के सकल घरेलू उत्पाद से कम से कम दो प्रतिशत की कटौती बिजली की कमी से होती है। इस परियोजना से पाकिस्तान में 10400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कोयला, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा ग्रिड बनाये जायेंगें।

पाकिस्तान और चीन ने 20 अप्रैल 2015 को CPEC के तहत 28 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि CPEC के तहत अर्ली हार्वेस्ट परियोजनाओं को तुरन्त शुरू कर सकने के लिए था इससे दोनों देश कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करेंगे क्योंकि आवश्यक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी थीं। इनमें शामिल है : पंजाब में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क, 870 मेगावाट सूकी कानारी (खैबर पख्तूनख्वा) जलविधुत परियोजना, 720 मेगावाट (AJK) जल विधुत परियोजना, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान 100 मेगावाट और हाइड्रो–चाइना 50 वाट के थाटा में तीन पवन ऊर्जा परियोजनाएं, काराकोरम हाईवे के दूसरे चरण के उन्नयन के लिए चीनी सरकार की रियायती ऋण, कराची–लाहौर मोटरवे (मुल्तान से सुक्कुर), ग्वादर पोर्ट पूर्व–बे एक्सप्रेसवे परियोजना और ग्वादर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामग्री का प्रावधान, ग्वादर बंदरगाह क्षेत्र में परियोजनाएं और चीन–पाकिस्तान संयुक्त कपास प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और चीन–पाकिस्तान संयुक्त समुद्री अनुसंधान केन्द्र की स्थापना। चेंगदू (चीन के सिचुआन प्रांत में) और लाहौर के बीच, झुहाई और ग्वादर और करमाय (शिनजियांग उड्घुर) और ग्वादर के बीच बहन–शहरों के संबंध की स्थापना पर प्रोटोकॉल के समझौते किए गए थे।

ग्वादर–नवाबशाह एलएनजी टर्मिनल और पाइपलाइन प्रोजेक्ट और वाणिज्यिक अनुबंध और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो परियोजना, पोर्ट कासिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र, झिरमिर पवन ऊर्जा परियेजना, थार ब्लॉक II 3.8 के लिए वित्तपोषण पर एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

CPEC के कार्यान्वयन के लिए चीन विकास निगम और हबीब बैंक लिमिटेड द्वारा एक वित्तपोषण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जलविधुत परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए वाप्दा, पीपीआईबी और चाइना थ्री गोरजेस कॉर्पोरेशन (सीटीजी) के बीच एक समझौता ज्ञापन और निजी जल विधुत परियोजना के विकास पर सिल्क रोड फंड पर भी हस्ताक्षर किए गए।

चीन के औद्योगिक और वाणिज्यक बैंक (ICBC) चीन की PCC और दाऊद पवन ऊर्जा परियोजना के लिए HDPPL और ICBC और HBL के बीच वित्तीय सेवा निगम पर एक फ्रेमवर्क समझौता, जिसमें चीनी निवेश और पाकिस्तान में औद्योगिक पार्को के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

चीनी निवेश में निम्न चुनौतियां शामिल हैं

चीनी निवेश के बारे में सफलता और गुणवत्ता रखरखाव की दर के बारे में आशंकाएं हैं। एक चीनी राज्य एजेंसी से जुड़े दो शोधकर्ताओं के अनुसार, 1990 के दशक के अंत में पूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं की वितरण दर, जो कि 74–79 प्रतिशत थी, अब 60 प्रतिशत से नीचे गिर गई है। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग 40 प्रतिशत चीनी निवेश परियोजनाएं या तो समय पर समाप्त नहीं हुई हैं या पूरी नहीं हुई हैं।

चीन द्वारा किए गए भारी निवेश में पिछले तीन से चार दशकों में अफ्रीका सहित इसके पड़ोसी देशों में, द्विपक्षीय निवेश सौदे आम तौर पर अपारदर्शी हैं। विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं में, स्थानीय स्वदेशी बाजारों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, पूरी तरह से चीनी सेवाओं और रसद पर जोर दिया गया है, यहां तक कि श्रम को चीनी मुख्य भूमि से लाया जाता है, वेतन सीधे उनके परिवारों को दिया जाता है, चीन द्वारा सीधे प्रदान किए जा रहे श्रम का भरण–पोषण, सभी सामग्री और विनिर्माण सामग्री को मुख्य भूमि से लाना, जो कि निवेश पैकेज से भुगतान किया जाएगा। इस तरह, हालांकि ऐसा लगता है कि एक बड़ा निवेश किया जाता है, लेकिन एक भी युआन पूरे विकास प्रक्रिया के दौरान चीन को नहीं छोड़ता है।

पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आधिकारिक भ्रष्टाचार, उग्रवाद, अलगाववाद और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है, फिर भी चीन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश कर रहा है। बावजूद इसके कि पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर चीनी नागरिकों या अधिकारियों को निशाना बनाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं बलूची विद्रोहियों के द्वारा ग्वादर बंदरगाह पर ऐसा ही हमला, चीनी राष्ट्रपति की यात्रा के साथ हुआ। पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) से चीन काफी परेशान है, जो पिछले दो वर्षो में सैकड़ों चीनी लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। चीन का लक्ष्य 226 ऐसे क्षेत्रों का विकास करना, जो गलियारे के दायरे में आते हैं, और अविकसितता से ग्रस्त हैं और उनका विकसित होना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के पास उइगर विद्रोहियों के प्रशिक्षण शिविर, झिंजियांग में आतंकवादी आयाम को हल कर सकता हैं। चीन अपने ज्यादातर मुस्लिम उत्तर–पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में जातीय उइगर मुस्लिमों की हिंसा से चिंतित है और उसे डर

है कि कट्टरपंथी अलगाववादी एवं उइगर आतंकवादी पाकिस्तान के तालिबान के सदस्यों के साथ मिलकर लड़ सकते हैं।

सी0पी0ई0सी0 पर भारत की चिंताएं

भारत दक्षिण एशियाई देशों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सार्क देशों की सकारात्मक उपस्थिति, सार्क सम्मेलन के दौरान काठमांडू में मोदी द्वारा निभाई गई भूमिका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए किए गए नेतृत्व के कई दौरे जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ निकटता; और चीन के साथ लगातार संवाद, इन सभी ने भारतीय रणनीतिक और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण गतिशीलता ला दी है। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि चीन द्वारा प्रस्तावित रेशम मार्ग का खुले तौर पर समर्थन करने से कुछ क्षेत्रों में भारत की संप्रभु स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, जिनमें से कुछ क्षेत्रों का दावा चीन खुद करता है, खासकर अक्साई चिन क्षेत्र और अरूणाचल प्रदेश में, इसलिए अब तक एक पारंपरिक रुख अपनाते हुए भारत ने इस परियोजना के बारे में अपना आरक्षण व्यक्त किया है, क्योंकि प्रस्तावित CPEC पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित क्षेत्र से होकर गुजरेगा। हाल ही में हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का अभी इस परियोजना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि यह भारत के हितों के खिलाफ है। हालांकि, तेजी से बदल रहा क्षेत्रीय वातावरण भारतीय नीति निर्माताओं को कुछ अन्य विकल्प भी प्रदान करता है। मोटे तौर पर, भारत के पास जवाब देने के लिए दो विकल्प हैंः पहला है कि या तो भारत द्वारा इस परियोजना में शामिल होकर आर्थिक लाभ कमाया जाये और अपने विवादों से आगे बढ़कर सम्बन्धों को नए सिरे से शुरू किया जाये और दूसरा विकल्य यह है कि भारत इस परियोजना से बाहर रहकर विरोध जारी रख सकता है।

हालांकि CPEC के भारत की विदेश नीति पर विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। जिसमें सबसे अधिक प्रभावित भारत–पाकिस्तान संबंध होंगें क्योंकि यह गलियारा उत्तरी पाकिस्तान में गिलगित–बाल्टिस्तान (जीबी) के क्षेत्र से होकर गुजरता है और यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जिसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने दावे किए हैं। अक्टूबर 1947 में पूर्व रियासत (जम्मू एवं कश्मीर) के भारतीय संघ में प्रवेश के बाद से नई दिल्ली ने भारत के लिए पूरे क्षेत्र का दावा किया है और केवल इस्लामाबाद के साथ विवाद को सुलझाने पर जोर देता है। भारत 1972 के शिमला समझौते को लागू करता है, जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल किया जाना है। इसके विपरीत, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर कई प्रस्तावों को लागू करता है और पूर्व रियासत को विवादित क्षेत्र मानता है, उसके अनुसार जिसकी संबद्धता जनमत संग्रह द्वारा तय की जानी चाहिए। कश्मीर विवाद 1947 से भारत और पाकिस्तान ने एक–दूसरे के खिलाफ लड़े गए चार युद्धों में से तीन का कारण रहा है।

CPEC का उद्देश्य पाकिस्तान में आर्थिक विकास में सुधार करना है। हाल के वर्षो में पाकिस्तान आर्थिक विकास में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में कमजोर रहा है। बेहतर आर्थिक विकास से पाकिस्तान के सैन्य खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। यह संभवतः भारत के साथ हथियारों की दौड़ में और इजाफा करेगा। अब तक भारत के साथ आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के प्रयासों ने पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के प्रतिरोध पर ध्यान दिया है। 1999 के लाहौर प्रक्रिया और 2004 के समग्र वार्ता से जुडे राजनीतिक तालमेल को 1999 के कारगिल युद्ध जैसे सैन्य कारनामों और 2009 के मुंबई हमलों जैसे बड़े आतंकवादी हमलों से कम करके आंका गया हैं। चीनी समर्थन से आर्थिक रूप से मजबूत पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में बहुत कम रूचि होगी एवं पाकिस्तान तब और अधिक बलपूर्वक कश्मीर विवाद को विदेश नीति के एजेंडे पर रख सकेगा , जैसे कि उसने 2014/15 में रूक–रूक कर किया है और अभी भी करने की कोशिश कर रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद। एक सशक्त पाकिस्तान सुरक्षा बलों की बढ़ती शक्ति के साथ भारत में आतंकी हमले करने बजाए कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्षमता के साथ उठा सकता है और ऐसी स्थिति में खेल पाकिस्तान के हाथों में होगा और यदि भारत–पाकिस्तान संघर्ष में चीनी नागरिकों पर हमला किया जाता है या बलोच अलगावादियों द्वारा चीनी रक्षा कर्मियों पर हमला होता है तो भारत–चीन के संबंध भी खराब हो सकते हैं क्योंकि बलोचिस्तान के लोग भारत का समर्थन करते नजर आते है। इस परिदृष्य में CPEC के राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव लंबे होंगें। इस मामले में CPEC के पाकिस्तान के लिए होने वाले सकारात्मक आर्थिक प्रभाव एक सैन्य निर्माण को बढ़ावा देंगें, जिससे भारत के साथ संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

दूसरी ओर, एक सकारात्मक परिदृश्य भी बोधगम्य है जिसका प्रभाव चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों पर पड़ सकता हैं। चीन के पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध कई वर्षो से अत्यंत सकारात्मक हैं और इसे ''हिमालय की तुलना में अधिक ऊँचा और समुद्र की तुलना में गहरा जैसी रूपात्मक परिधि में वर्णित किया गया है। हालांकि निकट विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ भी पाकिस्तान के भारत के साथ विवाद सबसे ऊपर है वहाँ या उन मुद्दों पर चीन पाकिस्तान के लिए उम्मीद के मुताबिक विश्वसनीय भागीदार नहीं है अर्थात् चीन पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं करता है। सबसे पहले, चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति का समर्थन नहीं करता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीयकरण के जरिए मामले को सुलझाना चाहता है इसके विपरीत चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ है जिनका मानना है कि विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किया जाना चाहिए और यह रूख भारत की स्थिति से मेल खाता है। दूसरा, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान बीजिंग भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। तीसरा, भारत–चीन संबंधों में 1990 के दशक से काफी सुधार हुआ है और इस सब की एक बड़ी वजह यह है कि भारत एक बड़ा बाजार है जिसे चीन नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में तनाव अभी भी जारी है, उदाहरण के लिए हिमालय में सीमा मुद्दे अनसुलझे ही रहे हैं और यदि हाल ही में हुए घटनाक्रम को देखा जाए तो भारत के साथ चीन के संबध अपने सबसे खराब दौर में हैं फिर भी, दोनों देशों ने हाल के वर्षो में अपने राजनीतिक और आर्थिक सहयोग में काफी विस्तार किया है, उदाहरण के लिए ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) में भागीदारी के माध्यम से

अंतरराष्ट्रीय बातचीत के दौर में वे नियमित रूप से जारी है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत और पाकिस्तान का प्रवेश नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सहयोग को और भी मजबूत करेगा।

दक्षिण में बदलता शक्ति संतुलन एवं भारत

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दक्षिण एशिया में विकास परियोजनाओं के लिए जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका प्राथमिक दाताओं में से एक रहे हैं, हालांकि जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे अन्य देशों ने हाल के वर्षो में अधिक से अधिक भूमिका निभाई है एवं भारत सहित दक्षिण एशियाई देशो को महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान की। इस बीच, क्षेत्रीय रणनीतिक और आर्थिक अभिनेता के रूप में चीन के उद्धव ने एशिया में कनेक्टिविटी की संभावनाओं को फिर से खोल दिया है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसने भारत के पड़ोस में सुरक्षा वातावरण को बदल दिया है, भारत के पड़ोसियों के साथ बीजिंग के बढ़ते सहयोग ने नई दिल्ली में बेचैनी पैदा कर दी है। वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ किसी भी बढ़ती शक्ति की तरह, चीन अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है और अपने निकटवर्ती क्षेत्र से परे अपने लाभ को बढ़ाता है। स्वाभाविक रूप से, जैसा कि दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ता है, भारत को अपने सबसे बड़े पड़ोसी के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने और क्षेत्र में अपनी प्रमुखता बनाए रखने के लिए क्षेत्र में बढती प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

भारत ने चीन की वाणिज्यिक पहलों को अपनी सामरिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है जो अक्सर भारत के हितों के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। BRI कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और वित्त अवसंरचना विकास के लिए धन प्रदान करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। दक्षिण एशिया में, BRI उपमहाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन–भारतीय प्रतियोगिता को रेखांकित करता है।

भारत ने नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करना शुरू कर दिया है। BRI पर आज तक के अपने सबसे मजबूत रूख में, भारत ने बेल्ट एंड रोड फोरम में भाग न लेकर अपने विरोध को चिह्नित किया जिसे चीन ने मई 2017 में आयोजित किया था। आधिकारिक बयानों में, भारत ने पहले ही पारदर्शिता और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया, और नई दिल्ली ने क्षेत्रीय संप्रभुता के बारे में चिंताओं के कारण चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का विरोध किया। इसके जबाव में भारत को अपनी परियोजनाओं में पूरे दिल से मजबूत होकर काम करना चाहिए, जैसे कि उत्तर दक्षिण आर्थिक गलियारा, साथ ही प्रोजेक्ट मौसम, अपने प्राचीन समुद्री मार्गो को पुनर्जीवित करने की एक क्षेत्रीय पहल और देशों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ अपने विस्तारित पड़ोस को भी महत्व देना चाहिए। भारत को चाबहार बंदरगाह को विकसित करने पर अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि यह ''पाकिस्तान के माध्यम से पारगमन की अनुपस्थिति में, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस और उससे आगे के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, चाबहार सुदृढीकरण एक खोयी हुई विकास प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने तथा चीनी विकास प्रक्रिया का मुकाबला करने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में कार्य करती है जो कि दक्षिण एशिया में मौजूद नाजुक संतुलन को कमजोर कर सकती है। इस तरह की परियोजनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि यह विकास की गतिविधि को सही अर्थो में विकसित करेगी बजाय इसके कि संसाधनों को उपयोग करने के लिए बाहरी शक्तियों को दिया जाए , और निकासी में संसाधन एक बड़ी शक्ति द्वारा समाप्त हो जाए, जिससे सहायता की आड़ में अधिक अभाव और शोषण होगा।

निष्कर्ष

CPEC से पाकिस्तान में आर्थिक तौर पर बहुत उम्मीदें रखी जा रही हैं। परियोजना को किस हद तक आगे बढ़ाया जायेगा या बढ़ाया जा सकता है यह अभी तक स्पष्ट नही है क्योकि अभी तक आधिकारिक घोषणाओं और वास्तव में पाकिस्तान में चीनी परियोजना पर खर्च किये गए धन के बीच एक अंतर रहा है। इस दृष्टि से परियोजना में गंभीर खामियां है जबकि CPEC पाकिस्तानी व्यवसायों को किस प्रकार प्रभावित करेगा तथा देश के भीतर के छोटे एंव घरेलु उद्योग CPEC से किस प्रकार प्रभावित होंगे इस संबंध में आंकडों की अभी तक कमी है लेकिन अभी तक के आँकड़े नकारात्मकता ही प्रदर्शित कर रहे हैं लेकिन इन सबके बावजूद यदि देखा जाए तो CPEC का आर्थिक तर्क सबसे मजबूत है लेकिन रणनीतिक रुप से परियोजना के बारे में कुछ कहा जाना अभी जंल्दबाजी होगी। हांलाकि अभी बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद तथा आंतरिक विरोध पर क्या कदम उठाता है ये देखने लायक होगा क्योंकि पाकिस्तान के भीतर भी परियोजना को लेकर बलोचिस्तान तथा खैबरपख्तूनख्वा प्रांतो में दिन व दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है जो परियोजना के लिए अच्छा संकेत नहीं है ।

भारत के लिए, जबकि इसे सी.पी.ई.सी. का विरोध जारी रखना चाहिए, इस क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बदलने की या इससे घबराने की जरुरत नहीं है, इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग का क्रम बहुत कम है यह एक ऐसे रिश्ते का मृत्युंजय हो सकता है जो दशकों से भारत के पक्ष में एक कांटा बन गया है जिसे हर भारतीय भी चाहता है आर्थिक मार्चे पर, जबकि चीन बीसीआइएम योजना के माध्यम से भारत को ओबीओआर का हिस्सा बनाबे के लिए दबाब डाल रहा है भारत ने बहुत ही समझदारी से प्रलोभन का विरोध किया है सीपीइसी अब तक जिस तरह से सामने आया है, वह भारत के रुख को सही साबित करता है। वास्तव में जब तक स्पष्ट नियम नहीं बनाये जाते और अस्पष्टता को पूरी ओबीओआर परियोजना से समाप्त नही किया जाता तब तक भारत के लिए इसमें कूदना नासमझी होगी। भारत को अपने पड़ोसियों के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी व्यवस्था की पेशकश करने के लिए इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ काम करना होगा। आज तक, नई दिल्ली क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण को पहचानने, आरंभ करने तथा कार्यान्वित करने में धीमा रहा है। हालांकि भारत ने जापान जैसे देशों की योजना पर काम किया है लेकिन प्रगति बहुत कम हुई है। नई दिल्ली को अपने रणनीतिक लक्ष्यों की रक्षा के लिए चीनी प्रतिक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण साझेदारों को अपनाने तथा अपने नेतृत्व वाली कनेक्टिविटी पहलों का विकल्प प्रदान करने के लिए तत्काल एक संरचित रूपरेखा की आवश्यकता है ताकि वह दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बना रहे।

सन्दर्भ सूची

1. Small Andrew. The China Pakistan Axis Asia's new geopolitics India, 2015.
2. Ravikant, China Pakistan economic corridor: bar or boom for India New Delhi India, 2020.
3. Chaudhry, dr. Shabir, is CPEC economic corridor or a strategic game plan us, 2017.
4. Sharma Bal, Kishan Kundu, Nivedita Das, China's one belt one road initiative, challenges and prospects New Delhi India, 2016.
5. Chaudhry Dr. Shabir. Economic growth or a debt trap for Pakistan United Kingdom, 2018.
6. Jain BM. South Asia conundrum: The great power Gambit Britain, 2019.
7. Macaes Bruno. Belt Road: A Chinese world order United Kingdom, 2019.
8. Wolf, Siegfried O. The China Pakistan economic corridor of the belt and road initative concept context and assessment Belgium, 2020.
9. Debnath Madhumanti. Strategik implications of the China Pakistan economic corridor, 2016.
10. Ludden Davi. India and Sourth Asia Asia report n°297 China-Pakistan economic corridor: opportunities and risks Belgium, 2018.
11. World Focus "Bharat Pakistan ke beech Takrav" may 2019.
12. Singh lt gen PK PVSM, AVSM (RETD), China-Pakistan economic corridor (CPEC): connecting the dots 2017.
13. Fayyaz Muhammad. China-Pakistan economic corridor (CPEC): the road to Indian Ocean and its geopolitical implications for the india pakistan strategic relations Khyber Pakhtunkhwa, pakistan, 2018.
14. Sanyal Rajib Kumar. Sino-Pak trade corridor, boon or bane amity university, Kolkata, 2019.
15. Ghiasy, Richard SU. FEI and Saalman, Lora, the 21st century maritime silk road (United Kingdom), 2018.
16. Khurana, Gurpreet S. India as a challenge to China's belt and road initiative
17. Chowdhury Sounak. The China-Pakistan economic corridor- a challenge to India's security
18. Kaushik Manish Prashant. CPEC, Afghanistan and India's concern, 2019.